

बॉर्डर न्यूज मिरर

“खबरों से समझौता नहीं”

पटना, वर्ष: 7 , अंक: 180 , बुधवार, 12 अगस्त 2026 मूल्य: 5:00, पृष्ठ:8 9471060219, 9470050309 www.bordernewsmirror@gmail.com



स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग संपन्न

03

शहीद रामगोविंद सिंह के 84वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा

04

सिद्धि विनायक के द्वार पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा एसएस राजामौली की फिल्म...

07

संक्षिप्त समाचार

वंदे मातरम् के जयघोष के साथ हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक



नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए संसदीय दल की ‘मंगल मिलन’ बैठक शुरू हो गई। बैठक की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ के जयघोष के साथ हुई। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी समेत एनडीए के अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी की इंस्टाग्राम वीडियो में देशवासियों से अपील, हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हों- पीएम मोदी ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया। उन्होंने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। पीएम ने कहा- 15 अगस्त को आन-बान-शान से मनाएं और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें। विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराए।

पुणे-सतारा हाईवे पर कार ट्रक से टकराई, चार युवकों की दर्दनाक मौत, दोगंभीर

पुणे (एजेंसी)। महाराष्ट्र में शिरवल के पास पुणे-सतारा हाईवे पर हुए एक भयानक सड़क दुर्घटना में चार युवकों की मौत पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि, यह भयानक हादसा तब हुआ जब झड़वर ने कार पर से अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन हाइवे के डिवाइडर से टकराकर पलट गई।

बेंगलुरु के होटल में शख्स ने 2 बेटियों की गला दबाकर हत्या की

बेंगलुरु (एजेंसी)। बेंगलुरु के एक 5-स्टार होटल में दो बच्चियों के शव बेड पर मिले, जबकि उनके पिता गंभीर हालत में टॉयलेट में मिले। पुलिस के मुताबिक, 40 साल के एसजी इमरान ने पहले अपनी 10 और 5 साल की बेटियों की गला घोटकर हत्या की और फिर चाकू से अपना गला काटकर आत्महत्या की कोशिश की। होटल सिक्योरिटी ने उसे मणिपाल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर है।

गांजा पीकर पलाइंट उड़ा रहा था एअर इंडिया का पायलट, दूसरे टेस्ट में हुई पुष्टि

नई दिल्ली (एजेंसी)। एयर इंडिया की फ्लैगशिप एअर इंडिया का पायलट की पोस्ट-पलाइंट स्क्रीनिंग में इसकी पुष्टि हुई है, जिसकी लेबरिपोर्ट मंगलवार को जारी हुई। 300 फीट के अचानक आए झटके और यात्रियों के घायल होने के मामले में एक बड़ा और चौकाने वाला खुलासा हुआ है। इस उड़ान के पायलट-इन-कमांड (मुख्य पायलट) का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है।

भारत की चीन को दो टूक

अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा, इसे कोई बदल नहीं सकता



नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश और अरुणाचल प्रदेश से जुड़े दो अहम मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारतीय दूत दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान से मुलाकात की। भारत ने उन्हें द्विपक्षीय यात्रा के साथ-साथ दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स आउटरीच सत्र के लिए भी आमंत्रित किया है।

दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत-चीन सीमा संबंधी मामलों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीमा की स्थिति का असर दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ता है।

चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश को लेकर आई प्रतिक्रिया पर पूछे गए सवाल के जवाब में रणधीर जायसवाल ने भारत की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक ऐसी वास्तविकता है जो स्वयं स्पष्ट है और इस निर्विवाद सच्चाई को कुछ भी नहीं बदल सकता।

अब ‘वंदे मातरम्’ का अपमान होगा अपराध

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून हुआ लागू



नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का अपमान करना अब अपराध माना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से ‘वंदे मातरम् बिल’ को मंजूरी मिलने के बाद आज मंगलवार, 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह कानून बन गया है।

इस कानून के लागू होने से राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को जानबूझकर गाने से रोकना या उसमें बाधा डालना अपराध माना जाएगा। इस बिल से इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रीय गान को मिलती है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026 अब कानून बन गया है। यह कानून ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ के बराबर का दर्जा देता है। राज्यसभा ने इस बिल को 29 जुलाई को मंजूरी दी थी। वहीं लोकसभा में यह बिल 30 जुलाई को पास हुआ था। अब राष्ट्रपति ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह विधेयक, कानून बन गया है।

फसल बीमा योजना

अब किसानों को क्लेम के वक्त नहीं होगी परेशानी

राजस्थान सरकार ने खरीफ के लिए नए दिशा-निर्देश जारी



जयपुर (एजेंसी)। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पॉलिसियों को जारी करने से पहले वेरिफिकेशन सुनिश्चित करना होगा। राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये निर्देश खरीफ 2026 से लागू होंगे।

होगा पॉलिसी का वेरिफिकेशन

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि जिन किसानों ने ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन नहीं लिया है, उनकी पॉलिसी का वेरिफिकेशन निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिसूचित बीमा कंपनी की होगी। उन्होंने बताया कि ऋणी किसानों की पॉलिसी सुनिश्चित करते समय किसानों की सहमति नहीं लेने तथा वास्तविक बोई गई फसल का बीमति फसल से मिलान न होने के कारण क्लेम भुगतान के समय विवाद उत्पन्न होते हैं। इसका समाधान पॉलिसी जारी करने के समय ही फसल की वेरिफिकेशन किया जाना जरूरी है।

देश के कई राज्यों में मानसून का तांडव

हिमाचल में अब तक 157 लोगों की मौत, 886 करोड़ का नुकसान

मप्र-राजस्थान-उप्र समेत 6 राज्यों में 48 घंटे से लगातार बारिश

हिमाचल में चलती कार पर पत्थर गिरे, 259 सड़कें बंद, चमोली में बादल फटा, ब्रिज, बीआरओ कर्मचारी और वाहन बहे

नई दिल्ली/ देहरादून/ भोपाल/ लखनऊ (एजेंसी)। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। उग्र में भी लगातार बारिश जारी थी गंगा-यमुना उफान पर थी। हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही दिन-ब-दिन गहराती जा रही है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लगातार हो रही भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने राज्य में भारी तबाही मचाई है।



30 जून से 9 अगस्त तक की अवधि में राज्य भर में प्राकृतिक आपदाओं और हादसों में अब तक 157 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि राज्य को करीब 886 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है।

भोपाल में दो दिन से बारिश जारी है। यहां 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। स्कूलों में दो दिन की छुट्टी कर दी गई। शहर में 1,000 से ज्यादा घरों के आसपास 5 फीट तक पानी भर गया।

वाराणसी घूमने आए महाराष्ट्र के कारोबारी की होटल में मौत



पहुंवा था। यहां तीन दिनों तक उन्होंने गंगा स्नान किया और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर काशी का भ्रमण किया।

इस दौरान 9 अगस्त की देर रात होटल में अचानक से कारोबारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे बीएचयू के टॉमा सेंटर में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। दूसरे दिन परिजनों ने हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद मां बेटी होटल लौट आए, जहां दोनों ने सुसाइड कर लिया।

आस्था का अनोखा अंदाज!

सुमित की साइकिल से 26 हजार किमी की यात्रा, 21 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग कवर



संदेश देने की प्रेरणादायक मुहिम भी रही। सुमित ने करीब एक साल तक साइकिल से देश भ्रमण करते हुए 26 हजार किलोमीटर का सफर तय किया।

21 राज्यों में पहुंचकर 12 ज्योतिर्लिंगों व चार धामों के दर्शन किए। 25 अगस्त 2025 को शुरू हुई उनकी यात्रा 10 अगस्त 2026 की शाम अपने गांव लौटने के साथ पूरी हुई। खास बात यह रही कि घर वापसी के दौरान सुमित ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल कांवड़ यात्रा भी की।

जयपुर पुलिस के 22 पुलिसकर्मी सस्पेंड

संसद में गतिरोध कायम, हंगामे के चलते स्थगित

एक सिपाही ऐसा भी जो 4 साल से गायब, 38 बार नोटिस के बाद भी नहीं आया

संसद में गतिरोध कायम, हंगामे के चलते स्थगित

एक सिपाही ऐसा भी जो 4 साल से गायब, 38 बार नोटिस के बाद भी नहीं आया

एक सिपाही ऐसा भी जो 4 साल से गायब, 38 बार नोटिस के बाद भी नहीं आया

जयपुर (एजेंसी)। वंदी की नौकरी में अनुशासन सबसे जरूरी है। अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाती है। पुलिस में भले ही लचीला व्यवहार नजर आ सकता है लेकिन आमी में तो बिल्कुल नहीं। वंदी की अहमियत जानते हुए भी जयपुर के 22 पुलिसकर्मी पिछले लंबे समय से अपने ही अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते रहे। आखिर पुलिस कमिश्नर ने सख्ती दिखाई और 22 पुलिसकर्मीयों को सस्पेंड कर दिया। बिना सूचना के लंबे समय से गैरहाजिर-जयपुर आयुक्तालय में तैनात कई पुलिसकर्मी बिना सूचना के गैरहाजिर चल रहे थे। कोई एक साल से गैरहाजिर था तो कोई दो साल से।

सीएम सुवेंदु के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग



कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के हेलिकॉप्टर की कोलाघाट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद वे सड़क मार्ग से केशपुर के लिए रवाना हो गए। घटना की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लाक के सांसदों ने मंगलवार को एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर

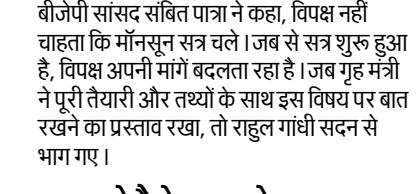
संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने भी आ गए। प्रियंका गांधी के

लोकसभा में केरल-नाम परिवर्तन विधेयक, 2026 पारित



संसद के मानसून सत्र संसद में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। हंगामे के बीच लोकसभा में केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित हुआ। हंगामे के बीच लोकसभा में दो बिल बिना चर्चा के पास हो गए। इनमें केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) बिल, 2026 शामिल है। अब संसद से राहुल को ‘भागना’ नहीं चाहिए- इस बीच केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अब संसद से ‘भागना’ नहीं चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

विपक्ष नहीं चाहता कि मानसून सत्र चले: सांसद सबित पात्रा



बीजेपी सांसद सबित पात्रा ने कहा, विपक्ष नहीं चाहता कि मानसून सत्र चले। जब से सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष अपनी मांगें बदलता रहा है। जब गृह मंत्री ने पूरी तैयारी और तथ्यों के साथ इस विषय पर बात रखने का प्रस्ताव रखा, तो राहुल गांधी सदन से भाग गए।

दस बच्चे पैलेट गन से घायल हुए: सांसद डीपल यादव

समाजवादी पार्टी की सांसद डीपल यादव ने कहा, हम दोनों मुद्दों पर बयान चाहते हैं, लेकिन गृह मंत्री सदन में आकर बयान देने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरटीआई से मिली जानकारी से पता चला है कि कम से कम दस बच्चे पैलेट गन से घायल हुए हैं।

नीलाम पत्र के बड़े बकायादारों पर प्रशासन का शिकंजा

» गिरफ्तारी वारंट जारी, 48 नीलाम पत्र देनदार पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

बीएनएम@ मोतिहारी

जिला प्रशासन ने नीलाम पत्र वाद के तहत बड़े बकायादारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि नीलाम पत्र से संबंधित मामलों में बकाया राशि की वसूली को लेकर प्रशासन गंभीर है। इसी क्रम में कई बड़े बकायादारों की गिरफ्तारी के लिए सक्षम स्तर से वारंट जारी किया गया है। जिन बकायादारों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, उनमें सलोनी ट्रेडर्स एवं राइस मिल, पूनछपरा, संजीव कुमार पांडेय (हिंदू चक्रिया) पर 13.56 लाख रुपये, मेसर्स दुर्गा वजय मिल, हरपुर (आदापुर) के राइस शंकर प्रसाद पर 11.67 लाख रुपये, लोकेश शाह (धड़हरवा) पर 10.11 लाख रुपये, प्रो. श्री वैष्णी एग्रीफीड्स के ओमप्रकाश प्रसाद (अमवा) पर 13.53 लाख रुपये, गोल्ड ड्रेसेज एवं सिंगार स्टोर के मुकेश कुमार (कुंडवा चैनपुर) पर 10.08 लाख रुपये तथा सैयद गल्ला भंडार के परवेज आलम (बेला चमही) पर 14.98 लाख रुपये की देनदारी शामिल है। इसके अलावा सिकंदर राय एवं शैल राय (हरिहारा) पर 11.09 लाख रुपये, मेसर्स मुस्कान मोबाइल के सोनू कुमार पर 11.28 लाख रुपये, मेसर्स एसीसी ब्रिक्स एंड कंपनी, बोकोकला के रजनीश कुमार सिंह पर 15.94 लाख रुपये, कांति देवी (कौड़िहार बड़ा टोला) पर 11.06 लाख रुपये, सरिता देवी (कौड़िहार चौक) पर 17.58 लाख रुपये, सोनेश्वर शाह (रक्सौल) पर 11 लाख रुपये, प्रिंस कुमार गुप्ता (नागा रोड) पर 11.75 लाख रुपये, योगेंद्र शर्मा (पनटोका) पर 11.07 लाख रुपये तथा श्याम

कुमार (आश्रम रोड, रक्सौल) पर 10.66 लाख रुपये की देनदारी है। इसी प्रकार मेसर्स एएस रोडवेज के ईश्वरचंद्र प्रसाद (माटिआरिया) पर 12.31 लाख रुपये, सुभाष प्रसाद (रानीछपरा) पर 15.50 लाख रुपये, विकास कुमार (रामपुरवा, मोतिहारी नगर) पर 27.95 लाख रुपये, सुनील कुमार गुप्ता की आटा चक्की दुकान (जमला रोड, बनियापट्टी) पर 10.20 लाख रुपये, मेसर्स मोबाइल म्यूजिक के दिनेश प्रसाद (नकछेद टोला) पर 11.48 लाख रुपये तथा मेसर्स जगदम्बा कंस्ट्रक्शन के अशोक कुमार सिंह (बलुआ टाल) पर 38.18 लाख रुपये की देनदारी है। मेसर्स सत्री स्टील फर्नीचर, बलुआ टाल के सत्री कुमार पर 12.78 लाख रुपये, मेसर्स ओम ट्रेडर्स के दीपक कुमार (छत्तौनी) पर 11.28 लाख रुपये, रूपेश कुमार (कवलपुर चौक) के शंकर कलेक्शन पर 10.08 लाख रुपये, मेसर्स चम्पारण ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के रंजन कुमार सिंह (गुलबारा, मधुबन) पर 12.86 लाख रुपये, नरेश राय (मिठनपुरा) पर 13.05 लाख रुपये, जगन्नाथ राय (सरैया, जगिराहां) पर 10.04 लाख रुपये, हरेंद्र राय (जगिराहां) पर 10.20 लाख रुपये तथा हीरो प्लाई ऐस ब्रिक्स इंडस्ट्रीज की अरुन्नी खातून (बड़कुरवा) पर 15.74 लाख रुपये की देनदारी है। प्रशासन के अनुसार, सभी संबंधित बकायादारों के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट संबंधित थानों के माध्यम से तामील करा दिया गया है। पुलिस प्रशासन भी इन मामलों में गिरफ्तारी को लेकर गंभीर है। प्रशासन ने बताया कि नीलाम पत्र के अन्य मामलों में अब तक 48 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, लंबित नीलाम पत्र मामलों में बकाया राशि की वसूली के लिए आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर एसएसबी ने चलाया जागरूकता अभियान



बीएनएम@ मोतिहारी

वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ और हर घर तिरंगा अभियान के तहत 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), मोतिहारी की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार के निदेशन में वाहिनी के कार्यक्षेत्र के विद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सीमावर्ती गांवों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं और आम लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन किया। इससे पूरा वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया। एसएसबी के अधिकारियों और

जवानों ने लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। साथ ही तिरों के साथ सेल्फी लेकर उसे हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की गई। अधिकारियों ने लोगों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव की भावना व्यक्त करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों, विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की।एसएसबी अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ आम लोगों के बीच राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव की भावना को मजबूत करना है।

केविवि के मीडिया अध्ययन विभाग में नवप्रवेशित विद्यार्थियों का प्रबोधन कार्यक्रम

बीएनएम@ मोतिहारी

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय (केविवि) के मीडिया अध्ययन विभाग में 2026 सत्र के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉ. अंजनी कुमार झा ने की। इसमें बीए-एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार के एकीकृत पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, पत्रकारिता के मूल्यों और मीडिया के बदलते स्वरूप की जानकारी दी गई।

स्वागत उद्बोधन में विभाग के आचार्य डॉ. सकेत रमण ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विभाग एक परिवार की तरह है और विद्यार्थियों का इसमें शामिल होना उनके लिए नए सफर की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि



पत्रकारिता जीवन मूल्यों को सहेजने और सामाजिक सरोकारों के साथ आगे बढ़ने की यात्रा है। विभाग विद्यार्थियों को इस यात्रा में हरसंभव सहयोग देगा।

आचार्य डॉ. परमात्मा कुमार मिश्र ने पत्रकारिता के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विभाग में उपलब्ध लेब और स्टूडियो की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद बेहद आवश्यक है।

बीएनएम इम्पैक्ट : अनुमंडल प्रशासन बैकफुट पर, 15 अगस्त तक रोकी गई राशन घोटाले की प्राथमिकी अब दर्ज

लिखित आदेश के बावजूद एफआईआर पर रोक को लेकर एसडीओ-थानाध्यक्ष के विरोधाभासी बयानों के बीच बॉर्डर न्यूज मिरर के अंग्रेजी संस्करण में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने दर्ज किया मामला

बीएनएम@ सागर सूरज

मोतिहारी। पकड़ीदयाल अनुमंडल में कथित राशन घोटाले से जुड़े जिस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का लिखित आदेश जारी होने के बावजूद कार्रवाई 15 अगस्त तक रोक दिए जाने का मामला सामने आया था, उसमें अब बड़ा बदलाव आया है।

बॉर्डर न्यूज मिरर के अंग्रेजी संस्करण में मामले से संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

प्रभारी पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

मामला जनवितरण प्रणाली के विक्रेता चन्नू साह पर सरकारी राशन के कथित गबन और लाभुकों के फर्जी हस्ताक्षर इस्तेमाल करने के आरोप से जुड़ा है। इससे पहले पकड़ीदयाल अनुमंडल पदाधिकारी मंगला कुमारी ने 6 अगस्त 2026 को पत्र संख्या 2049 जारी कर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में 7 अगस्त

को मधुबन थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया था।

लेकिन इसके बाद प्राथमिकी दर्ज होने के बजाय मामला अचानक रोक दिए जाने की बात सामने आई। सोमवार को मधुबन थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार पांडेय ने बताया था कि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई 15 अगस्त तक रोक दी गई है। थानाध्यक्ष ने इसके लिए पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी के आदेश का हवाला दिए जाने की बात भी कही थी।

यही बयान पूरे मामले में विवाद का कारण बना था।

दूसरी ओर, अनुमंडल पदाधिकारी मंगला कुमारी ने थानाध्यक्ष के इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने प्राथमिकी रोकने अथवा उसे 15 अगस्त तक टालने का कोई निर्देश नहीं दिया। एसडीओ ने थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने से मना करने के आरोपों को भी निराधार बताया।

अब इसी विवाद के बीच प्राथमिकी दर्ज हो जाने से मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

फर्जी हस्ताक्षर की जांच का

पंचायत समिति की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली व्यवस्था पर जोर

बीएनएम@ रामगढ़वा

प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख रीता देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों में तेजी लाने तथा आम लोगों की बुनियादी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली आपूर्ति, नल-जल योजना सहित विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली, सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक माहौल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया। विभिन्न पंचायतों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की सड़क, नल-जल



योजना सहित अन्य लंबित विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को सदन के समक्ष रखा। जनप्रतिनिधियों ने समस्याओं के त्वरित निषादन की मांग की। अधिकारियों ने उठाए गए मामलों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में बीडीओ राकेश कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी इंंदरजीत दास, सीओ अमित कुमार, उपप्रमुख अरविंद पांडेय, पीएचसी प्रभारी डॉ. नितेश

ध्वज सिंह, मनरेगा पीओ कुमार प्रसांत, कनीय अभिन्यात मनोज कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, मुखिया शिवचंद्र यादव, नसीबुल हक, धीरज कुमार गुप्ता, समिति सदस्य लालबाबू यादव, टैंगर ठाकुर, आजाद आलम, प्रियंका देवी सहित प्रखंड क्षेत्र के सभी मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

जमीन विवाद में मोतिहारी न्यायालय सख्त, हरसिद्धि अंचलाधिकारी समेत तीन अधिकारी तलब

फर्जी पर्चें से जमाबंदी और जमीन कब्जे के आरोप पर न्यायालय का बड़ा एक्शन, हरसिद्धि अंचलाधिकारी समेत डीएम और एसडीओ को किया तलब

बीएनएम@ सागर सूरज

मोतिहारी। हरसिद्धि अंचल में रैयती जमीन की कथित फर्जी जमाबंदी और कब्जे के प्रयास से जुड़े मामले में मोतिहारी न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुनीत कुमार तिवारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हरसिद्धि अंचलाधिकारी अरविंद कुमार चौधरी, पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव और अरराज के अनुमंडल पदाधिकारी को तलब किया है।

मामला आवेदक बृजकिशोर चौबे की रैयती जमीन से जुड़ा है। उनके अधिवक्ता दिवाकर ने न्यायालय के समक्ष आरोप रखा कि एक कथित फर्जी पर्चों के आधार पर जमीन की जमाबंदी कायम की



गई। खास बात यह है कि आवेदक पक्ष के अनुसार, पूर्व में पदस्थापित अंचलाधिकारी इसी दावे को फर्जी बता चुके थे। जबकि उसी आधार पर जमाबंदी कायम किए जाने का आरोप है।

यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। सवाल यह है कि जिस दस्तावेज को पहले फर्जी बताया गया, वह बाद में



किस आधार पर वैध मान लिया गया और उसके आधार पर जमाबंदी कैसे कायम हुई? इसी बिंदु पर राजस्व अभिलेखों और पूरी प्रक्रिया की जांच जरूरी हो गई है।

आवेदक का आरोप है कि कथित जमाबंदी के आधार पर उनकी रैयती जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। जमीन पर झोपड़ी रखवाकर कब्जा जमाने की कोशिश

यदि थानाध्यक्ष का सोमवार को दिया गया बयान सही था तो प्राथमिकी रोकने का निर्देश किस स्तर से आया था? यदि एसडीओ ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था, तो थानाध्यक्ष ने उनके नाम का हवाला क्यों दिया? और जिलाधिकारी के निर्देश का हवाला दिए जाने की बात कितनी सही थी?

इन सवालों का स्पष्ट जवाब अभी सामने आना बाकी है। इस संबंध में जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव का पक्ष जानने के लिए दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

खबर के बाद पत्रकार को धमकी देने का भी आरोप- इसी बीच अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों को लेकर खबर प्रकाशित होने के बाद आवेदक पत्रकार ने अनुमंडल पदाधिकारी पर धमकी देने तथा दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी देने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, मामले की शिकायत जिलाधिकारी, सहयोग पोर्टल और अन्य वरीय अधिकारियों से भी की गई है।

पत्रकार की ओर से भ्रष्टाचार के

विरुद्ध उठाई गई आवाज को दबाने का प्रयास किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

इधर, एसडीओ ने पत्रकार को धमकी देने समेत लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया है।

अब जांच की बारी- प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि सरकारी राशन के कथित गबन, लाभुकों के फर्जी हस्ताक्षर और अन्य आरोपों में कितनी सच्चाई है।

साथ ही, प्राथमिकी दर्ज करने के लिखित आदेश के बावजूद कार्रवाई में हुई कथित देरी और 15 अगस्त तक प्राथमिकी रोकने के लिए एताए गए कथित निर्देश की भी जांच जरूरी हो गई है।

सनद रहे कि मामला दर्ज होना आरोपों की पुष्टि नहीं है। अब पुलिस जांच में ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और जम्मैदारी किसकी तय होती है। वैसे क्या थानाध्यक्ष ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की या पहले के डेट में की यह भी जांच का विषय बन सकता है।

स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग संपन्न



बीएनएम@ मोतिहारी

जिला प्रशासन के तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रगान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रतिभागी टीमों का चयन मंगलवार को स्क्रीनिंग के माध्यम से किया गया। शहर स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी विद्यालयों तथा संस्थाओं के प्रतिभागियों ने राष्ट्रगान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। स्क्रीनिंग के दौरान छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति एवं पारंपरिक लोककला पर आधारित आकर्षक और मनोहारी प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल ने प्रस्तुतियों के आधार पर श्रेष्ठ प्रतिभागी टीमों

का चयन किया। निर्णायक मंडल में मुंशी सिंह कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार, संजय पांडेय, शैलेंद्र कुमार सिन्हा एवं अभय अनंत शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन आदित्य मानस ने किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन गिरि सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। राष्ट्रगान के लिए चयनित टीमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान, समाहरणालय परिसर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस केंद्र, अनुमंडल कार्यालय सदर, जिला परिषद, गांधी संग्रहालय, नगर निगम कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर अपनी प्रस्तुति देंगी। वहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए चयनित टीमें स्वतंत्रता दिवस की संध्याकालीन बेला में महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में अपनी कला के विविध रंग बिखेरेंगी।

गई। पेट्रोल और मिर्च पाउडर से हमला करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

अधिवक्ता श्री दिवाकर के अनुसार, न्यायालय ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की विभिन्न स्तरों से जांच की आवश्यकता महसूस की है। इसी क्रम में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया गया है।

अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल केवल जमीन के मालिकाना हक का नहीं है, बल्कि राजस्व अभिलेखों में कथित बदलाव और जमाबंदी कायम करने की प्रक्रिया का भी है। यदि जांच में यह साबित होता है कि कथित फर्जी दस्तावेज को आधार पर जमाबंदी कायम हुई, तो

उस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है।

उल्लेखनीय है कि जमीन से जुड़े विवादों में राजस्व अभिलेख ही किसी पक्ष के दावे का महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। ऐसे में अभिलेखों की वैधता पर सवाल उठने के बाद उसी आधार पर जमीन पर कब्जे का प्रयास होने का आरोप पूरे प्रकरण को गंभीर बना देता है।

अब सबकी नजर न्यायालय में संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यों और राजस्व अभिलेखों की जांच पर है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कथित फर्जी पर्चें और जमाबंदी की वास्तविक स्थिति क्या है तथा इसमें किसी स्तर पर अनियमितता हुई या नहीं।

राजकीय डिग्री महाविद्यालय परसौनी में छह नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों ने संभाला कार्यभार

बीएनएम@ सीतामढ़ी

जिला के परसौनी प्रखंड स्थित राजकीय डिग्री महाविद्यालय में मंगलवार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा। महाविद्यालय में छः विषयों के छह नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर (डॉ.) मधुर कुमार ने बताया कि सभी सहायक प्राध्यापको ने प्रथम दिन कॉलेज पहुंचकर अपना योगदान दिया। योगदान में पठन-पाठन का माहौल और बेहतर होने की उम्मीद है। प्राचार्य प्रोफेसर (डॉ.) मधुर कुमार ने सभी नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा



तथा समाजशास्त्र विभाग से कुमारी ऐश्वर्या शामिल हैं। नए सहायक प्राध्यापकों के आने से कॉलेज में पठन-पाठन का माहौल और बेहतर होने की उम्मीद है। प्राचार्य प्रोफेसर (डॉ.) मधुर कुमार ने सभी नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा

कि इनके आने से महाविद्यालय के शैक्षणिक विकास को नई गति मिलेगी। इस गरिमामयी अवसर पर कॉलेज के अर्थपाल डॉ. शारदानंद सहनी सहित महाविद्यालय के अन्य कर्मी और प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। सभी ने नए सहायक प्राध्यापकों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

संक्षिप्त समाचार

मोहिउद्दीन नगर पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
न्यायिक हिरासत में भेजा



बीएनएम@ समस्तीपुर। मोहिउद्दीन नगर थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक पुराने आपराधिक मामले का अभियुक्त शामिल है, जबकि दो आरोपी उत्पाद एवं मद्यनिषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामले में नामजद थे। इस संबंध में थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि पुलिस ने थाना कांड संख्या 105/21 के अभियुक्त चंदन कुमार सिंह, पिता स्व. तनिक, को बिचला मलाही, थाना बाढ़, जिला पटना से गिरफ्तार किया। वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त में बाहर था। वहीं, दूसरी कार्रवाई थाना क्षेत्र के मदुदाबाद पंचायत अंतर्गत शिवना गांव में की गई। यहां से थाना कांड संख्या 227/26 के उत्पाद एवं मद्यनिषेध अधिनियम के प्राथमिकी अभियुक्त सजी कुमार, पिता मुना चौधरी तथा मोनू कुमार, पिता स्व. मनोज चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद मंगलवार को सभी आरोपियों को पुलिस अधिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की लगातार कार्रवाई से आपराधिक एवं शराब से जुड़े मामलों में सलिलत लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। थाना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

बांका में वज्रपात से तीन महिलाओं की मौत
किशोर और किशोरी गंभीर, बारिश के दौरान बाँड़ा गांव में हुआ हादसा

बीएनएम@ बांका। चांदन प्रखंड अंतर्गत सुईया थाना क्षेत्र के बाँड़ा गांव में मंगलवार को बारिश के दौरान हुई वज्रपात की घटना में तीन महिलाओं की मौत हो गयी। वहीं वज्रपात की चपेट में आने से एक किशोर और एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गयी। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटोरिया पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीन महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। घायल किशोर और किशोरी का अस्पताल में उपचार जारी है। बताया गया कि मंगलवार को क्षेत्र में बारिश हो रही थी। इसी दौरान बाँड़ा गांव में अचानक वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में पांच लोग आ गये। घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटोरिया पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने तीन महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। वज्रपात की घटना में जान गंवाने वाली महिलाओं की पहचान बाँड़ा गांव निवासी शंभू यादव की 45 वर्षीय पत्नी कुसमी देवी, टीपन यादव की 35 वर्षीय पत्नी रिंकु देवी और राजेंद्र यादव की 38 वर्षीय पत्नी रेणु देवी के रूप में हुई है। तीनों महिलाएं आपस में गौतनी थीं। एक ही घर आए एक ही परिवारिक रिस्ते से जुड़ी महिलाओं की एक साथ मौत की खबर से ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गयी।

बिहार सरकार ने 628.32 करोड़ रुपए किए मंजूरे
पटना मेट्रो निर्माण कार्यों में आगेगी तेजी

बीएनएम@ पटना। पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने 628.32 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। यह रकम वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना के तहत उपलब्ध कराई गई है। सरकार की इस मंजूरी से मेट्रो के निर्माण से जुड़े जरूरी कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन मजबूत होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के साथ बाहरी वित्तीय एंजिसियों के सहयोग से परियोजना के लिए फंडिंग की जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, स्वीकृत राशि पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) के माध्यम से परियोजना पर खर्च की जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल मेट्रो के मुख्य निर्माण कार्यों में किया जाएगा। इससे चल रहे कामों की गति रखने और परियोजना की रफ्तार बनाए रखने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 23 जुलाई 2026 को बिहार के लिए विशेष सहायता योजना के तहत कुल 2925 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसकी पहली किस्त के रूप में 2628.32 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी राशि में से 628.32 करोड़ रुपए पटना मेट्रो परियोजना के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

पटना जिले में 2 साल से एक ही जगह तैनात पुलिस अधिकारियों का तबादला

24 घंटे के भीतर नव-पदस्थान में योगदान का कड़ा निर्देश
बीएनएम@ पटना। जिले के नगर पश्चिमी क्षेत्रांतर्गत पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), पटना द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत कुल 73 पुलिस सब-इंस्पेक्टरों (SuboFno) और पदाधिकारियों का तबादला विभिन्न थानों एवं पुलिस प्रतिय्ठानों में कर दिया गया है। यह प्रशासनिक फेरबदल उन पुलिस पदाधिकारियों के लिए किया गया है जो पिछले दो वर्षों से अधिक समय से एक ही थाने या प्रतिष्ठान में पदस्थापित थे। पुलिस महकमे में कार्यपालनी को अधिक चुस्त-दुरुस्त और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर किया जा सके। इस तबादला सूची के अंतर्गत दानापुर, फूलबारीशरीफ, बेउर, पालीगंज, बिहटा, नेउरा, मनरे और नौबतपुर जैसे प्रमुख थानों के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। जारी किए गए आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरण प्राप्त सभी 73 पुलिस अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापित स्थान पर योगदान सुनिश्चित करेंगे।

बिहार में शराबबंदी पर NCAER रिपोर्ट से गरमाई सियासत
NDA में भी अलग-अलग रुख

बीएनएम@ पटना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के दस साल पूरे होने के बीच इस नीति को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और आर्थिक बहस तेज हो गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एल्कोहल इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की हालिया रिपोर्ट में बिहार में शराबबंदी की समीक्षा करते हुए इसे खत्म कर नियंत्रित विक्री की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराबबंदी के कारण राज्य को आबकारी राजस्व के बड़े स्रोत की मांग है। वहीं केंद्रीय मंत्री और LJP (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने शराबबंदी खत्म करने के बजाय दूसरे माध्यमों से राज्य का राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और HAM(S) प्रमुख जीवन राम मांझी ने गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने की बात कही है।

बीएनएम@ रामगढ़वा

प्रखंड के रामगढ़वा बाजार स्थित कोठी रोड, वार्ड नंबर 9 में मंगलवार तड़के 18 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आइसक्रीम बेचकर जीवनयापन करने वाले गुड्डू कुमार, पिता भज्जू साह के रूप में हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम के साथ मोतिहारी एसएपी प्रीतेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामले में एक महिला सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

परिजनों के अनुसार गुड्डू कुमार सोमवार की रात करीब 8 बजे घर से चीनी खरीदने के लिए निकला था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर रात 10 बजे के बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। आसपास के रिस्तेदारों और परिचितों के यहां पता किया गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

पहचान लापता गुड्डू कुमार के रूप में हुई। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर रामगढ़वा थाने की पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। इसके साथ ही मोतिहारी एसएपी प्रीतेश कुमार भी पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे

को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। इसके साथ ही मोतिहारी एसएपी प्रीतेश कुमार भी पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे

रामगढ़वा में आइसक्रीम विक्रेता का शव मिलने से सनसनी, 2 हिरासत में

एफएसएल टीम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर की जांच, हत्या की आशंका



शहीद रामगोविंद सिंह के 84वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा

बीएनएम@ पटना

प्रशांत किशोर ने विद्यालय के पुनर्निर्माण का लिया संकल्प



स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद रामगोविंद सिंह के 84वें शहादत दिवस पर पटना स्थित शहीद रामगोविंद सिंह बालिका विद्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों, बुद्धिजीवियों और स्थानीय नगरिकों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर शहीद की प्रतिमा एवं चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शहीद रामगोविंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। श्रद्धांजलि सभा के बाद प्रशांत किशोर ने शहीद रामगोविंद सिंह बालिका विद्यालय का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की जर्जर आधारभूत संरचना और कमरों की स्थिति का जायजा लिया। विद्यालय की मौजूदा स्थिति को देखकर उन्होंने चिंता जताई और स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों तथा स्थानीय लोगों से भी जानकारी ली। विधायक ने कहा कि यह विद्यालय शहीद रामगोविंद सिंह के स्मृति और उनके बलिदान से जुड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है। इसकी स्थिति में सुधार करना जरूरी है। उन्होंने विद्यालय के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण का संकल्प लेते हुए कहा कि इसके लिए जल्द पहल की जाएगी। उन्होंने आशवासन दिया कि विद्यालय में छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल और आवश्यक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी जरूरी प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने विद्यालय के विकास की पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि ऐतिहासिक विद्यालय को जल्द बेहतर स्वरूप मिलेगा।

गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर SDM ने किया प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण

» अधिकारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश

बीएनएम@ समस्तीपुर

गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पटोरी अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार पांडेय ने मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने माधोपुर सररी, रसलपुर, बिशनपुर बेड़ी, सुल्तानपुर एवं घटहटोल क्षेत्रों का भ्रमण कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने पटोरी अंचल अधिकारी अभिषेक कुमार, मोहनपुर अंचल अधिकारी संतोष कुमार, मोहिउद्दीन नगर अंचल अधिकारी विवेक कुमार सिंह एवं राजस्व अधिकारी मोहिउद्दीन नगर सृष्टि सागर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहे

बिहार में वेतन संकट की समस्या जल्द दूर होगी: अशोक चौधरी

बीएनएम@ पटना

बिहार में कुछ कर्मचारियों और अन्य लोगों को समय पर वेतन नहीं मिलने की शिकायतों के बीच मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ लोगों का भुगतान समय पर नहीं हो पाया है और इसे सरकार के सामने मौजूद समस्या बताया। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। अशोक चौधरी ने कहा कि वेतन भुगतान में निश्चित तौर पर कुछ दिक्कतें हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने वित्त मंत्री के भरोसे का हवाला देते हुए कहा कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर अशोक चौधरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वह लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं हैं और उनकी पार्टी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करती। उन्होंने बिहार में हुए प्रदर्शनों का उदाहरण देते हुए



कहा कि यहां प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान संयमित रहैया अपनाया। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार को भी छात्रों से जुड़े मामलों को गंभीरता से देखना चाहिए। इस दौरान तेजस्वी यादव की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र का मुद्दा भी उठा। तेजस्वी यादव ने उर्दू और अरबी शिक्षकों के तबादले को लेकर सरकार से सवाल किया था। इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार सभी वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े मामलों को देख रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय उर्दू की स्थिति क्या थी, यह सभी जानते हैं।

बिहार के प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास को मिलेगी रफ्तार

» पर्यटन मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात

बीएनएम@ पटना

बिहार के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास को गति देने के लिए पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्र को भेजी गई विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं पर जल्द निर्णय लेने और सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। पर्यटन मंत्री ने केंद्रीय बजट घोषणा 2024-25 के तहत भेजे गए प्रस्तावों की जानकारी देते हुए कहा कि स्वीकृति मिलने से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य समर्थक तरीके से शुरू किए जा सकेंगे। उन्होंने गयाजी-बोधगया

और नालंदा-राजगीर के लिए तैयार व्यापक गंतव्य रणनीति एवं विकास योजनाओं की भी जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी। बिहार सरकार ने गयाजी-बोधगया के समग्र विकास के लिए 1,080 करोड़ रुपये और नालंदा-राजगीर के लिए 1,050 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है। दोनों योजनाओं से संबंधित विस्तृत आधारभूत विश्लेषण प्रतिवेदन केंद्र सरकार को उपलब्ध कराया जा चुका है। योजनाओं का उद्देश्य धार्मिक, ऐतिहासिक और

सांस्कृतिक स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना और पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा देना है। पर्यटन मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लागू होने से बिहार के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को बेहतर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ स्थानीय रोजगार और पर्यटन आधारित आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

अकबरनगर थाना क्षेत्र के आलमगीर गांव में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष के छह लोग घायल हो गए। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल आसमा खातून ने बताया कि विवाद की शुरुआत साझा गली में दरवाजा लगाने को लेकर हुई। उनका आरोप है कि पाटीदारों ने गली में जबरन दरवाजा लगा दिया था। इसी रास्ते से दोनों परिवारों के लोगों का आवागमन होता था। रास्ता बाधित होने को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और बाद में मामला मारपीट तक पहुंच गया। आसमा खातून के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर परिवार की ओर से डायल-112 पर सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने मामले के समाधान के लिए दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया था। आरोप है कि मोहम्मद जियाउल बाद में थाना

पहुंचे, लेकिन उस समय कोई अधिकारी मौजूद नहीं था और उन्हें कुछ देर बाद आने को कहा गया। पीड़िता का आरोप है कि थाना से लौटने के बाद विपक्षी पक्ष ने गली में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी-डंडे से लैस लोगों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। इस दौरान आसमा खातून, उनके बेटे, भतीजी समेत छह लोग घायल हो गए। तीन घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत नहीं दी गई थी। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस गांव में स्थिति के समाधान के लिए दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया था। आरोप है कि मोहम्मद जियाउल बाद में थाना



और बाढ़ से संबंधित आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों को पॉलीथिन शीट, पशुचार, नाव सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार रखने को कहा गया। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने तथा बाढ़ की संभावित स्थिति

गोविंदगंज पुलिस की कार्रवाई, दो फरार वारंटी गिरफ्तार

बीएनएम@ अरेराज/गोविंदगंज

गोविंदगंज थाना क्षेत्र के मझरिया पासवान टोला निवासी स्वर्गीय पासवान के 64 वर्षीय पुत्र कपिल



अपराध नियंत्रण एवं फरार वारंटियों की गिरफ्तारी को लेकर गोविंदगंज पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर दो वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपितों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक सचिदानंद पांडेय ने बताया कि न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में पुलिस टीम ने छापेमारी कर दोनों वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान हरसिद्धि थाना क्षेत्र के जगापाकड़ शर्मा टोला, वार्ड संख्या-1 निवासी अशोक शर्मा के 30 वर्षीय पुत्र राकेश शर्मा तथा

देव पासवान के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कामजी प्रक्रिया पूरी कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि फरार वारंटियों एवं आपराधिक गतिविधियों में सलिलत लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Monsoon Session: Govt offers Amit Shah statement in Parliament opposition doesn't relent



New Delhi, Agency: Govt Monday agreed to a debate in Parliament on the recent student protest and home minister Amit Shah's statement on the issue, but it failed to break the impasse as Congress insisted that all its demands, including PM Modi's apology for alleged police excesses against protesters and a statement on embezzlement of Ram temple funds, be met.

"Congress and Rahul Gandhi have been demanding a statement from Shah from day one (of Parliament's monsoon session). Govt is ready to hold a discussion and give a detailed response. I request Congress not to walk out during his (Shah's) statement. It should not be scared and run away," parliamentary affairs minister Kiren Rijiju said.

The opposition, however, persisted with its protests, leading Rijiju to accuse Rahul of shifting goalposts. The leader of the opposition said all the issues raised by Congress are "non-negotiable".

It appears that his intention is to prevent the House from functioning. Rahul Gandhi, do not run away from discussion. We are prepared to discuss every issue inside the House," Leader of the House in Rajya Sabha J P Nadda said after Rahul was joined by Congress president Mallikarjun Kharge in rejecting govt's proposal. Nadda also denied that police had fired at protesters on July 20.

Marred by opposition protests since the session began on July 20, except for an animated debate on the NEET paper leak and related issues, LS again faced a couple of adjournments Monday before Rijiju conveyed govt's proposal.

Rijiju had put forth govt's stand earlier at a meeting of floor leaders of different parties chaired by Speaker Om Birla, and some opposition MPs saw in it a bid to divide their ranks, as the minister made no commitment to the demand of a discussion on the theft of donations at Ram temple, a demand primarily taken by Samajwadi Party. The opposition has, however, so far not laid out the sequence in which they wanted the issues to be discussed. SP chief Akhilesh Yadav said the breach of faith of crores of devotees was not a normal issue and it must be discussed. Speaking to reporters later, both Kharge and Rahul said Shah must make a statement in Parliament on who authorised the "brutality" on students. Rahul said the country was not interested in Shah's "fantasy conversations" on general issues but wanted to know specifically if he ordered the shooting of pellet guns and use of nail-studded lathis on students. "Shah should come clean... We are seeking his resignation," he said. All three demands are non-negotiable, Kharge stressed, suggesting the stand-off is unlikely to end in days to come as monsoon session ends Aug 13. In a counter presser.

Nadda accused Rahul of misleading people by making a baseless allegation that shots were fired at student protesters during their march to Parliament on July 20. "Rahul has been disrupting the House for over 15 days by speaking lies and spreading confusion.

Images disturb me deeply': Congress' Sam Pitroda questions 'use of force' against Jharkhand students

New Delhi, Agency: Congress leader Sam Pitroda on Monday backed protesting students in Jharkhand as an agitation over alleged irregularities in JPSC and JSSC recruitment examinations intensified in Ranchi. Criticising the government's use of lathis, tear gas and water cannons, Pitroda called for "reform, accountability and compassion" as the protests entered their 18th day.

The development comes as the Jharkhand students' 'Vidhan Sabha gherao' march in Ranchi



on Monday saw police use lathis and water cannons to disperse protesters. The march was organised over alleged irregularities in examinations conducted by the Jharkhand Public Service



Commission (JPSC) and Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC).

The protesters are demanding, among other measures, the cancellation of the JSSC-Combined Graduate

Level (CGL) examination, a Central Bureau of Investigation (CBI) probe into alleged irregularities and reforms in the recruitment process.

In a series of posts on X, the Indian Overseas Congress (IOC) global chairman said the grievances of young people should be addressed through dialogue.

"The images from Ranchi disturb me deeply", he wrote.

Pitroda said students should not be met with force, calling them India's future and expressing solidarity with Jharkhand's

youth. In another post, Pitroda said, "Democracy requires governments to create space for peaceful dissent, dialogue and resolution.

Pitroda's remarks came after Congress leader Rahul Gandhi also condemned the police action and called for dialogue with the protesting students, urging the Jharkhand government to address their grievances. The Hemant Soren-led Jharkhand government is run by a JMM-led coalition in which the Congress is a partner.

New Parliament, PM house, why not new govt schools in villages' CJP's Dipke announces nationwide campaign

New Delhi, Agency: Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke has announced a nationwide campaign to improve government schools in villages, seeking to address the "neglect of rural educational infrastructure".

The campaign will be launched on August 15, with the CJP calling on citizens, parents and village leaders to work together to improve basic facilities in government schools.

Dipke said he would launch the initiative from his village in Hingoli, Maharashtra, by approaching the village head and requesting him to take steps to improve government schools there.

"The coming 15th August is our 80th Independence Day. But, if anything has been neglected or ignored the most in the last 80 years, it is the government schools in our villages," Dipke said on Monday. We have made a new Parliament, a new PM house. Why have we not been able to build new schools in our villages? Do we not consider the children of farmers and labourers the future of our country?" he asked. Dipke said children in villages continue to face difficulties in accessing schools and basic facilities such as drinking water and toilets.

Even today, village children have to walk a long distance to go to school. After going there, they don't find water or toilet facilities," he said, highlighting the difficulties faced by girls in particular. I feel that on this 15th August, if we should pay attention to anything, if we should make a new start, we should start by improving our government schools," he



said.

As part of the campaign, the CJP has appealed to sarpanches across the country to take up the task of improving government schools in their respective villages.

Dipke said he would personally approach the village head in Hingoli and urged other sarpanches to do the same in their villages.

The organisation has termed the initiative the "Sarpanch Challenge", under which it plans to publicly recognise village heads who improve their schools by sharing before-and-after photographs on its social media platforms and giving credit to the sarpanches concerned. We will give you credit so that after seeing you, after seeing the schools that you have improved, many other village heads also start improving schools in their villages," Dipke said.

The CJP has also called for a citizen-led social audit of government schools.

Parents whose children study in government schools have been asked to visit the institutions and check basic facilities, including electricity, clean drinking water, functional washrooms and mid-day meals.

You go to your children's

schools and see if basic facilities are available. See if there is electricity, water... Do your children get wash-room facilities? Do they get mid-day meals?" Dipke said.

He urged parents to record videos if basic facilities were unavailable. The CJP said it would soon issue a printable audit form through which citizens could record the facilities available at their children's schools and those that were missing.

The form will be shared through links on campaign videos on the CJP's official social media platforms and completed forms and video evidence can be emailed to the organisation.

The campaign aims to ensure that children of farmers and wage labourers studying in village schools have access to facilities comparable to those available to children in cities.

If not, you make videos of it. Because your children's schooling should be good. That is your fundamental right," Dipke said. Let us all make a promise to the children who live in villages that we will improve their schools. Together, we can do this," he said, concluding his video with the message, "Real India lives in villages.

Safari in snow leopard home? Conservationists say Ladakh is no Kaziranga

Srinagar, Agency: A safari car can roll past a rhino in Kaziranga. In Ranthambore, it can track a tiger. Put that car in Ladakh. For its elusive snow leopards - masters of camouflage in a landscape where survival depends on staying unseen - the question is whether tourism can get close enough to see them without making them disappear for good.

Ladakh has planned to introduce guided wildlife safaris on popular snow leopard and bird-watching trails, triggering warnings from conservationists that turning a fragile high-altitude wilderness into a tourist circuit could disturb wildlife, commercialise off-roading and open the door to roads, eateries and other tourism infrastructure. You cannot see a snow leopard from a jeep unless you do something illegal like placing bait or a sheep to lure it," said Dr MK Ranjitsinh, emeritus member of Wildlife Trust of India, who has spent nearly 50 years shaping conservation strategies and played a key role in framing the Wildlife (Protection) Act of 1972 and Project Tiger. Kaziranga is not Ladakh and



Ranthambore is not Ladakh. The ecology is completely different," he added.

In Ladakh's open valleys, vehicles can be visible from miles away. Vegetation is concentrated along valley bottoms, drawing animals there to feed and drink. "Are you taking a safari there?" he asked.

Ladakh is home to 477 of India's estimated 718 snow leopards - the country's largest population. It also supports more than 38 mammal species, 340 bird species and 1,800 vascular plant species. But spotting a snow leopard is a needle-in-a-haystack affair. Its thick, mottled coat melts into rocky slopes, while steep, remote terrain gives it a vast natural advantage. The Ladakh govt spokes person said lieutenant governor Vinai Kumar Saxena safaris modelled on national parks such as Kaziranga and Ranthambore, using specially designed open-back and guides.

Technology is helping ICICI Prudential Life bring down its savings cost-to-premium ratio

Mumbai: ICICI Prudential Life Insurance's sustained investment in technology and automation along with other cost optimisation initiatives has played a central role in bringing down its cost-to-premium ratio for the savings line of business to 13.6% in Q1-FY2027. It has reduced by 50 basis point over the previous year, even as the Company continues to scale its business.

Commenting on this, Mr. Ganessan Soundiram, Chief Technology Officer, ICICI Prudential Life Insurance, said, "At ICICI Prudential Life Insurance,



our investments in bolstering the Company's digital infrastructure have not only empowered our customers but also enabled us to deliver an enhanced customer experience across their policy life cycle.

We are leveraging AI,

analytics and platforms such as ICICI Pru Partner Stack, IPRU Edge, etc. to strengthen customer acquisition, distributor effectiveness, servicing and operational efficiency. When we built our technology stack, the goal was never automation for its

own sake. It was about taking out the friction and the cost that come from manual processes, so that savings get passed on more efficiently and customers get a faster, simpler experience. That same thinking is now helping us to improve operational efficiency.

India move will muddy border talks

Guwahati, Agency: China has hit back sharply at India for assigning standard names to 27 geographical locations in Arunachal Pradesh, with the state-run Global Times claiming these areas are in China's 'Zangnan' region - Beijing's term for Arunachal Pradesh and adjoining areas that it claims as part of Tibet Autonomous part.

The daily reiterated that Chinese foreign ministry spokesperson Guo Jiakun said at a routine press briefing on April 14 that the Zangnan region is China's territory and "China does not recognise the so-called 'Arunachal Pradesh' illegally set up by India. It is fully within China's sovereign rights for the Chinese govt to issue standard names for some of the places in Zangnan.

The reaction came three days after India's Survey of India updated its official map to identify 21 land areas, four passes, a high-altitude glacial lake and a 1962 war hero monument in Arunachal Pradesh, which govt said was an exercise to ensure the "correct identification" of places and enhance public awareness of their geographical and historical significance.

Global Times reported on Sunday night that the mapping by India came shortly after the 36th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on China-India Border Affairs (WMCC), held on Aug 6 in New Delhi, where officials from both sides discussed control, mechanism building and cross-border cooperation.